विचार बिन्दु

सही स्थान पर बोया गया सुकर्म का बीज ही समय आने पर महान फल देता है। -कथा सरित्सागर

भारत में बेरोज़गारी

भारत विश्व की सबसे ज़्यादा युवा आबादी वाला देश है। भारत की युवा आबादी (15-24 वर्ष): लगभग 24 करोड़ (240 मिलियन) है। हमारी तुलना में चीन में यह युवा आबादी थोड़ी कम अर्थात 22 करोड़ ही है। यह स्थिति किसी भी देश के लिए अत्यधिक हर्ष और गर्व का कारण होनी चाहिए। हम भारतीयों को भी इस बात पर गर्व है। लेकिन ज़रा ठहर कर सोचें तो हम पाते हैं कि यह स्थिति जितना गर्व प्रदान करती है उतनी ही चिंता भी पैदा करती है। बात को स्पष्ट करूं? अगर हम इस युवा आबादी की कार्य क्षमता का अर्थात जन सांख्यिकीय लाभांश पूरा उपयोग कर सकें तो देश का समठा विकास नई ऊंचाइयों को छू सकता है। लेकिन अगर हम इन 48 करोड़ हाथों को उपयुक्त रोज़गार न दे सकें और इनकी क्षमताओं का पूरा उपयोग न कर सकें तो न केवल विकास का हमारा सपना पूरा नहीं होगा, ये युवा भी कुण्ठित होकर एक बड़ी सामाजिक उथल-पुथल का कारण बन जाएंगे। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि देश में न केवल आर्थिक विकास हो, वह आर्थिक विकास रोज़गार सृजन में भी सक्षम हो। यहां यह बात भी ध्यान में रखने योग्य है कि भारत में आर्थिक विकास की दर पिछले कुछ वर्षों से 6 से 8 प्रतिशत के बीच रही है। देखने की बात यह है कि क्या इस आर्थिक विकास की कोई संगति हमारे रोज़गार सृजन से है?

भारत सरकार के पीरियॉडिक लेबर फोर्स सर्वे (PLFS) के नवीनतम उपलब्ध वार्षिक आंकड़ों (जुलाई 23 से जून 24) के अनुसार भारत में बेरोज़गारी की दर लगभग 3.2 प्रतिशत थी। इस दर में पुरुष और महिला बेरोज़गारी लगभग समान पाई गई। हाल के समय में पीएलएफएस के ये आंकड़े त्रैमासिक आधार पर भी ज़ारी किए जाने लगे हैं, और अक्टोबर-दिसम्बर 2025 के आंकड़े बताते हैं कि भारत में बेरोज़गारी दर 4.8 प्रतिशत थी। इसी अवधि में ग्रामीण बेरोज़गारी दर लगभग 4 प्रतिशत और शहरी बेरोज़गारी दर 6.7 प्रतिशत पाई गई। यहीं यह जान और समझ लेना भी ज़रूरी है कि भारत में बेरोज़गारी को तकनीकी रूप से परिभाषित करने का तरीका ऐसा है कि स्थित वाकई जितनी गम्भीर है उतनी गम्भीर नज़र नहीं आती है। तरीका यह है कि जिस व्यक्ति के पास न्यूनतम एक घण्टे का भी काम है वह सरकारी आंकड़ों में बेरोज़गार नहीं माना जाता है। तो ये 4.8 प्रतिशत लोग वे हैं जिनके पास एक घण्टे का भी रोज़गार नहीं है। लेकिन सोचिये कि जिस व्यक्ति के पास एक या दो घण्टे का रोज़गार है क्या वह उसे जीवित रखने के लिए पर्याप्त है? गरिमापूर्वक जीवित रहने की तो बात ही मत कीजिए।

अभी हम समग्र बेरोज़गारी की बात कर रहे थे। अब ज़रा युवा वर्ग (15-29 वर्ष) के रोज़गार की स्थिति भी जान लें। पीएलएफएस डेटा के अनुसार भारत में युवा बेरोज़गारी दर 10.2 प्रतिशत है जो वैश्विक औसत से थोड़ी कम है। वैसे कुछ अन्य सर्वेक्षण यह भी बताते हैं कि भारत में युवा बेरोज़गारी दर 14-15 प्रतिशत के आस पास है। अगर हम सरकारी आंकड़ों को पूरी तरह विश्वसनीय मान लें तो भी स्थिति चिंताजनक है। जो युवा शक्ति भविष्य की औद्योगिक, डिजिटल और हरित अर्थ व्यवस्था की रीढ़ हो सकती है, उसके पास काम ही न होना गम्भीर चिंता की बात है।

अभी हमने कुछ अलग-अलग लगने वाले मुद्दों की चर्चा की: भारत में बेरोज़गारी, भारत में युवा बेरोज़गारी और भारत में आंशिक बेरोज़गारी। आंशिक बेरोज़गारी से यहां आशय यह है कि जो लोग दिन में केवल एक घण्टा काम करते हैं वे आंशिक बेरोज़गार हैं। यही हम असंगठित और अनौपचारिक क्षेत्रों में काम करने वालों को और गिग वर्कर्स को भी याद कर सकते हैं। गिग वर्कर भले ही साथ आठ या इससे भी ज़्यादा घण्टे काम करते हैं और उनमें से अनेक ठीक-ठाक कमाई भी कर लेते हैं, उनके पास किसी तरह की सामाजिक सुरक्षा का न होना और हमेशा ही उन पर काम से बाहर कर दिये जाने की तलवार का लटका रहना उनकी स्थिति को चिंताजनक बना देता है।

> **भारत के पास बहुत बड़ी युवा शक्ति है। उसका सही उपयोग करके हम अपने देश को प्रगति की राह पर ले जा सकते हैं। युवा काम चाहते हैं। वे काम करने को तैयार हैं। ज़रूरत इस बात की है कि उन्हें काम करने के लिए प्रशिक्षित किया जाए और दो टूक शब्दों में यह भी समझा दिया जाए कि प्रगति की राह श्रम की सड़क से ही होकर गुज़रती है। अपनी शिक्षा व्यवस्था को सुधार कर और उसे भविष्य की ज़रूरतों के अनुरूप ढाल कर हम बेरोज़गारी की समस्या को हल कर सकते हैं।**

अब हम यह विचार करें कि भारत की आर्थिक प्रगति की दर ठीक-ठाक होने के बावज़ूद बेरोज़गारी की वजह क्या है? पहली बात तो यह कि हमारे यहां सेवा क्षेत्र का विकास अधिक हुआ है और उसमें रोज़गार के अवसर अपेक्षाकृत कम हैं। दूसरी बात तकनीकी प्रगति और स्वचालन है जिसने रोज़गार के अवसर कम कर दिए हैं। पहले जहां सौ कार्मिकों की ज़रूरत थी, अब बमुश्क़िल दस की ज़रूरत रह गई है। इसी के साथ यह भी जोड़कर देखना होगा कि हम बाज़ार की ज़रूरतों का प्रामाणिक आकलन करके तदनुसार अपनी शिक्षा को नियोजित कर पाने में असमर्थ रहे हैं। यह कहना भी बहुत क्रूर नहीं होगा कि हमारी शिक्षा व्यवस्था और बाज़ार की ज़रूरतों के बीच कोई संवाद है ही नहीं। परिणाम यह होता है कि रोज़गार के नए अवसर तो सृजित होते हैं लेकिन उन अवसरों का लाभ उठाने में सक्षम युवा हमारे पास नहीं होते हैं, भले ही उनके पास किसी विश्वविद्यालय की औपचारिक डिग्री होती है लेकिन वह डिग्री भावी नियोक्ता को काम की नहीं लगती।

पिछले दिनों एक समाचार आया था कि राजस्थान के 18 में से दस विश्वविद्यालयों में सारे के सारे पद रिक्त पड़े हैं। अकेले राजस्थान विश्वविद्यालय में, जो राजस्थान का सबसे पुराना और अग्रणी विश्वविद्यालय है 1016 शैक्षणिक पदों में से 608 पद रिक्त हैं। जोधपुर के एमबीएम इंजीनियरिंग संस्थान में शिक्षकों के सारे के सारे 147 पद रिक्त हैं। वहीं के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में शिक्षकों के 421 में से 308 पद खाली पड़े हैं। कोटा विश्वविद्यालय में 64 के 64 शैक्षिक पद खाली पड़े हैं। कहना अनावश्यक है कि इन खाली पदों के बावज़ूद ये संस्थान नियमित परीक्षाएं भी करवाते हैं और हर साल शिक्षितों की एक बड़ी फौज़ को कोई न कोई डिग्री देकर बाहर भी निकालते हैं। सोचने की बात यह है कि बिना शिक्षकों के पढ़ाई करने वाले ये युवा कितने काबिल होंगे? कोई इन्हें क्यों अपने यहां नियुक्त करेगा! हाथों में डिग्री थामे ये युवा या तो पूरी तरह बेरोज़गार रहेंगे या फिर 'चपरासी की नौकरी के लिए आए डिग्री धारी इंजीनियर जैसी किसी सनसनीखेज खबर का विषय बनकर रह जाएंगे।

बहुत बार यह कहा जाता है कि भारत का अधिसंख्य युवा पढ़ाई में मेहनत नहीं करता है या वह केवल ऐसी सरकारी नौकरी करना चाहता है जहां बहुत कम दक्षता से काम चल जाता है। हो सकता है ये बातें आंशिक रूप से सही हों। लेकिन ये आंशिक रूप से सही बातें हमारे नीति निर्माताओं को उनकी ज़िम्मेदारी से मुक्त नहीं कर सकतीं। क्यों नहीं अगले दस-पंद्रह बरसों की ज़रूरत का आकलन करके तदनुसार शैक्षिक ढांचे को व्यवस्थित किया जाए! क्यों न शिक्षा के नाम पर खुलने वाली महंगी दुकानों पर रोक लगाई जाए! क्यों न सरकारी शिक्षण संस्थानों की हालत सुधारी जाए! क्यों न शिक्षा व्यवस्था की पूरी बागडोर उनके हाथों में सौंपी जाए जो इसकी काबिलियत रखते हैं! क्यों न नेता और राजनीति कर्मी इस सारे काम से अपने को दूर रखें। उनके पास वैसे भी करने को बहुत सारे काम हैं। शिक्षा का काम इस क्षेत्र के विशेषज्ञों पर छोड़ दें तो उनकी बड़ी कृपा होगी। अभी तो हाल यह है कि इतिहास के मुद्दों पर भी विचार और फैसला वे करते हैं जिन्हें इतिहास का इ भी मालूम नहीं। वे ही यह तै करते हैं कि किस वैज्ञानिक को पाठ्यक्रम में रखा जाएगा, किसे हटाया जाएगा। वे ही इस बात का भी फैसला करते हैं कि अंग्रेज़ी साहित्य के पाठ्यक्रम में शेक्सपियर को पढ़ाया जाए या नहीं! जब यह सब हो रहा है तो इसकी परिणति भी वही हो सकती है जो हो रही है।

भारत के पास बहुत बड़ी युवा शक्ति है। उसका सही उपयोग करके हम अपने देश को प्रगति की राह पर ले जा सकते हैं। युवा काम चाहते हैं। वे काम करने को तैयार हैं। ज़रूरत इस बात की है कि उन्हें काम करने के लिए प्रशिक्षित किया जाए और दो टूक शब्दों में यह भी समझा दिया जाए कि प्रगति की राह श्रम की सड़क से ही होकर गुज़रती है। अपनी शिक्षा व्यवस्था को सुधार कर और उसे भविष्य की ज़रूरतों के अनुरूप ढाल कर हम बेरोज़गारी की समस्या को हल कर सकते हैं। दुनिया के बहुत सारे देशों ने ऐसा किया है। उनके उदाहरण हमारे सामने हैं। चुनाव हमें करना है, कि हम क्या चाहते हैं!

-अतिथि संपादक,
डॉ. दुर्गाप्रसाद अग्रवाल,
(शिक्षाविद और साहित्यकार)

विकसित राजस्थान @ 2047 का बजट और सशक्त नारी शक्ति

राजेंद्र राठौड़

राजस्थान की मरुधरा आज एक युगांतरकारी परिवर्तन की साक्षी बन रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व और उपमुख्यमंत्री व वित्त मंत्री दिया कुमारी द्वारा प्रस्तुत बजट विकसित राजस्थान 2047 के संकल्प को साकार करने वाला एक सुदृढ़ विजन डॉक्यूमेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास के मंत्र को आत्मसात करते हुए इस बजट में (गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति) को प्रगति का मुख्य आधार बनाया गया है। राजस्थान अपनी वित्तीय सीमाओं के भीतर रहते हुए एक कल्याणकारी राज्य और आर्थिक शक्ति के बीच संतुलन साध रहा है।

किसी भी प्रदेश की प्रगति का सबसे सटीक पैमाना उसकी जीडीपी और राजकोषीय अनुशासन होता है। आर्थिक समीक्षा 2026-27 के आंकड़े चौंकाने वाले और उत्साहजनक हैं। प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आकार अब 21 लाख 52 हजार 100 करोड़ रुपये अनुमानित है। यह आंकड़ा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पिछली सरकार के अंतिम वर्ष की तुलना में 41.39 अधिक है। यह वृद्धि दर दर्शाती है कि राजस्थान में निवेश और औद्योगिक गतिविधियों ने तेज रफ्तार पकड़ी है। एक आम राजस्थानी की औसत आय में भी अभूतपूर्व सुधार हुआ है।प्रति व्यक्ति आय जो पहले 1.67 लाख रुपये के आसपास थी, अब बढ़कर 2,02,349 रुपये तक पहुँचने का अनुमान है। अक्सर देखा गया है कि लोकलुभावन घोषणाओं के चक्कर में राज्य कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। लेकिन इस बजट में राजकोषीय घाटे को का मात्र 2.54 रखने का लक्ष्य रखा गया है, जो निर्धारित वित्तीय सीमाओं के भीतर एक बड़ी उपलब्धि है।

इस बजट का सबसे उज्ज्वल पक्ष नारी शक्ति पर केंद्रित निवेश है। सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि महिला सशक्तिकरण अब केवल नारों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसे वित्तीय स्वतंत्रता से जोड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री के विजन से प्रेरित होकर राजस्थान में 12 लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी की श्रेणी में शामिल हो चुकी हैं। बजट 2026-27 में इस मुहिम को और विस्तार देते हुए 5,000 लखपति दीदियों को 100 करोड़ रुपये की ऋण सहायता का प्रावधान किया गया है। यह छोटे उद्योगों और स्वयं सहायता समूहों के लिए संजीवनी साबित होगा।

कृषि सखी और पशु सखी को आधुनिक डिजिटल टैबलेट से लैस करना एक क्रांतिकारी कदम है। यह न केवल तकनीक को गांव की चौपाल तक पहुँचाएगा, बल्कि डेटा-आधारित खेती और पशुपालन को भी बढ़ावा देगा। सरकार ने लाडो प्रोत्साहन के भाव को बजट के केंद्र में रखा है। प्रदेश की 4.6 लाख बालिकाओं को जन्म से लेकर उच्च शिक्षा तक 1.5 लाख रुपये की किश्तवार सहायता प्रदान की जा रही है। 382 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों और 41 नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रावासों का कायाकल्प किया जा रहा है। यहां 3-फेज बिजली, वॉशिंग मशीन और ऑटोमैटिक रोटी मेकर जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं ताकि छात्राएं अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित कर सकें। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति और अनुसूचित जाति-जनजाति की छात्राओं के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के माध्यम से करोड़ों की वित्तीय सहायता सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जा रही है।स्वास्थ्य के क्षेत्र में राजस्थान ने आउट बाउंड पोर्टेबिलिटी शुरू कर देश में एक मिसाल पेश की है। अब राजस्थान की महिलाएं केवल प्रदेश के भीतर नहीं, बल्कि देशभर के 31,000 से अधिक संबद्ध अस्पतालों में मुफ्त इलाज करा सकेंगी।

मातृत्व सहायता राशि को बढ़ाकर 6,500 रुपये कर दिया गया है, जिसका लाभ लगभग 10 लाख गर्भवती महिलाओं को मिलेगा। इसके साथ ही, 1.22 करोड़ महिलाओं और किशोरियों को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन का वितरण मासिक धर्म स्वच्छता के प्रति सरकार की गंभीरता को दर्शाता है। महिला सुरक्षा के मोर्चे पर तकनीक और पुलिसिंग का एक हाइब्रिड मॉडल तैयार किया गया है। प्रदेश में 22,000 सीसीटीवी कैमरों का नेटवर्क स्थापित किया गया है। 500 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट्स और 65 एंटी-रोमियो स्क्वॉड की तैनाती ने जमीनी स्तर पर सुरक्षा का माहौल बनाया है। आंकड़ों के अनुसार, पिछले दो वर्षों में महिला अपराधों में 12 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है, जो इस रणनीति की सफलता का प्रमाण है।

बजट में महिला कर्मचारियों के लिए सरोगेसी और कमीशनिंग मदर्स को मातृत्व अवकाश (क्रमशः 180 और 90 दिन) देने का प्रावधान प्रगतिशील समाज की पहचान है। वहीं, मृत कर्मचारियों के आश्रितों में पुत्र वधू को शामिल करना पुरानी और रूढ़िवादी मान्यताओं को तोड़ने वाला एक बड़ा सामाजिक सुधार है। किसान सम्मान निधि में 10,900 करोड़ रुपये का निवेश और गेहूं पर 150 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस सीधे किसानों की क्रय शक्ति में वृद्धि करेगा। युवाओं के लिए भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता और समयबद्ध नियुक्तियां इस बजट की प्राथमिकता हैं।इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में27,860 करोड़ की लागत से 42,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण न केवल कनेक्टिविटी बढ़ाएगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगा।

वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए सरकार ने जो खाका खींचा है, वह संतुलित विकास की ओर इशारा करता है। कुल प्राप्तियां 3,14,455.38 करोड़ और कुल व्यय 3,69,123.33 करोड़ के साथ ही विकास कार्यों के लिए 56,691.82 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बजट 2026-27 राजस्थान को बीमारू राज्य की छवि से पूरी तरह बाहर निकालकर एक विकसित प्रदेश की श्रेणी में लाने का साहस रखता है। बुनियादी ढांचे पर भारी निवेश (27,860 करोड़ रुपये सड़कों के लिए) और साथ ही सामाजिक सुरक्षा (91 लाख लाभार्थियों को 28,400 करोड़ रुपये की पेंशन) के बीच का यह संतुलन काबिले तारीफ है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान अब केवल योजनाओं के बारे में नहीं सोच रहा, बल्कि परिणामों को डिलीवर कर रहा है। यदि इन घोषणाओं का धरातल पर क्रियान्वयन इसी गति से होता रहा, तो विकसित राजस्थान 2047 का लक्ष्य केवल एक सपना नहीं, बल्कि एक हकीकत होगा। यह बजट आधी आबादी के प्रति सम्मान, अन्नदाता के प्रति कृतज्ञता और युवाओं के प्रति विश्वास का एक साझा दस्तावेज है। यह राजस्थान की समृद्धि का नया अध्याय है।

राजेंद्र राठौड़, पूर्व मंत्री, राजस्थान।

रिसर्च एंड डेवलपमेंट में विदेशों पर निर्भरता और आमजन को आत्मनिर्भर भारत का भ्रम

ज़रूरत है आत्मविश्लेषण की

सुनील दत्त गोयल

भारत आज स्वयं को विश्वगुरु, आत्मनिर्भर राष्ट्र और वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करने की बात करता है, लेकिन यदि इन नारों की बुनियाद को परखा जाए तो सबसे कमजोर कड़ी अनुसंधान एवं विकास (रिसर्च एंड डेवलपमेंट) ही दिखाई देती है। यह एक कटु सत्य है कि भारत आज भी अपनी जीडीपी का लगभग 0.6 प्रतिशत ही रिसर्च पर खर्च कर रहा है, जबकि दुनिया के अधिकांश अग्रणी देश 3.5 से 4 प्रतिशत तक का निवेश इस क्षेत्र में करते हैं। सवाल यह नहीं है कि भारत के पास संसाधन नहीं हैं, बल्कि यह है कि क्या भारत की नीतिगत प्राथमिकताओं में रिसर्च वास्तव में शामिल है?

विडंबना यह है कि हम हर अंतरराष्ट्रीय मंच पर चीन, अमेरिका या यूरोप की तकनीकी बढ़त पर चर्चा करते हैं, लेकिन यह स्वीकार करने से कतराते हैं कि उनकी इस बढ़त का मूल कारण निजी क्षेत्र को खुली छूट और प्रोत्साहन देना है। भारत में आज भी रिसर्च को सरकारी प्रयोगशालाओं और सीमित सार्वजनिक संस्थानों तक सीमित रखने की मानसिकता हावी है। निजी क्षेत्र को संदेह की दृष्टि से देखा जाता है, मानो नवाचार केवल सरकारी फाइलों और समितियों में ही जन्म ले सकता हो।

यदि चीन का उदाहरण लें, तो तस्वीर और भी स्पष्ट हो जाती है। चीन न केवल रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर भारी निवेश करता है, बल्कि निजी कंपनियों को टैक्स छूट, अतिरिक्त डिडक्शन, सब्सिडी, सॉफ्ट लोन और सरकारी खरीद में प्राथमिकता जैसे कई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ देता है। कई मामलों में तो कंपनियों द्वारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च किए गए धन का बड़ा हिस्सा अलग-अलग रूपों में उन्हें वापस मिल जाता है। परिणाम यह है कि चीनी कंपनियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, ड्रोन टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट सिस्टम और साइबर क्षमताओं में तेज़ी से आगे बढ़ी।

इसके विपरीत भारत में निजी उद्योग को अक्सर यह संदेश मिलता है कि आप निवेश करें, जोखिम उठाएं, लेकिन भरोसा और अधिकार सरकार के पास ही रहेगा। यही कारण है कि देश का प्रतिभाशाली युवा और उद्योगपति अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्षमता का बड़ा हिस्सा विदेशों में इस्तेमाल करने को मजबूर होता है।

ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स-2025 के ताज़ा आँकड़े भारत की अनुसंधान एवं विकास स्थिति की एक मिश्रित तस्वीर पेश करते हैं। दुनिया भर में कुल रिसर्च एंड डेवलपमेंट खर्च लगभग 2.8 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँच चुका है, जिसमें एशिया की हिस्सेदारी लगभग 45 प्रतिशत है। चीन ने लगभग 785.9 बिलियन डॉलर और अमेरिका ने 781.8 बिलियन डॉलर शोध पर खर्च किए, जबकि भारत 75.7 बिलियन डॉलर के साथ शीर्ष-10 देशों में सातवें स्थान पर है। सतही तौर पर यह उपलब्धि उत्साहजनक लग सकती है, किंतु गहराई से देखने पर अंतर स्पष्ट दिखाई देता है - चीन भारत की तुलना में लगभग दस गुना अधिक निवेश कर रहा है। और जब खर्च को जीडीपी के अनुपात में देखा जाता है, तो भारत का निवेश लगभग 0.7 प्रतिशत तक सीमित है, जबकि दक्षिण कोरिया जैसे देश 5 प्रतिशत से अधिक जीडीपी शोध पर व्यय कर रहे हैं। यह अंतर केवल संख्या का नहीं, बल्कि तकनीकी प्रतिस्पर्धा और दीर्घकालिक रणनीतिक क्षमता का संकेतक है।

भारत में रिसर्च एंड डेवलपमेंट संरचना भी विश्लेषण योग्य है। कुल शोध व्यय का लगभग 64 प्रतिशत हिस्सा सरकार और सार्वजनिक संस्थानों से आता है, जबकि निजी क्षेत्र का योगदान लगभग 36 प्रतिशत है। इसके विपरीत, विकसित अर्थव्यवस्थाओं में निजी क्षेत्र अनुसंधान का मुख्य वाहक होता है। अमेरिका में बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियाँ, जापान में ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग तथा यूरोप में हेल्थकेयर और ऊर्जा क्षेत्र निजी निवेश के माध्यम से शोध को गति देते हैं। भारत में पेटेंट फाइलिंग में वृद्धि - 2024-25 में 68,176 आवेदन - एक सकारात्मक संकेत अवश्य है, और हाल में घोषित एक लाख करोड़ रुपये की प्रोत्साहन योजना भी दिशा दर्शाती है, परंतु जब तक जीडीपी के अनुपात में निवेश नहीं बढ़ता और निजी क्षेत्र की भागीदारी संरचनात्मक रूप से सुदृढ़ नहीं होती, तब तक वैश्विक तकनीकी प्रतिस्पर्धा में वास्तविक छलांग कठिन दिखाई देती है। तथ्य यह संकेत देते हैं कि भारत ने प्रगति की है, पर वैश्विक मानकों की तुलना में अनुसंधान-गहन अर्थव्यवस्था बनने के लिए अभी लंबा रास्ता तय करना शेष है।

सबसे चिंताजनक स्थिति रक्षा और रणनीतिक क्षेत्रों में दिखाई देती है। हाल ही में परमाणु पनडुब्बी निर्माण जैसी दीर्घकालिक योजनाओं की चर्चा सामने आई, जिनकी पूर्णता वर्ष 2038 के आसपास बताई जा रही है। यह सुनकर किसी भी जागरूक नागरिक के मन में सवाल उठना स्वाभाविक है कि 13-14 वर्षों बाद की दुनिया और युद्ध की प्रकृति कैसी होगी? क्या तब तक आज की तकनीक प्रासंगिक भी रहेगी? आज युद्ध केवल टैंक, तोप और पनडुब्बी तक सीमित नहीं है। आधुनिक युद्ध डेटा, सैटेलाइट, सेंसर, ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर नेटवर्क से लड़े जा रहे हैं। जब तक रक्षा उत्पादन और अनुसंधान में निजी क्षेत्र की पूर्ण भागीदारी को स्वीकार नहीं किया जाएगा, तब तक भारत समय के साथ कदम नहीं मिला पाएगा। केवल सरकारी संस्थानों के भरोसे रक्षा तकनीक विकसित करने का मॉडल अब पुराना और अप्रभावी साबित हो चुका है।

चीन ने हाल के वर्षों में सैकड़ों, बल्कि कुछ आकलनों के अनुसार हजारों निगरानी सैटेलाइट अंतरिक्ष में स्थापित किए हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य विजिलेंस, सुपरविजन और इंटेलिजेंस है। इन्हीं क्षमताओं के बल पर वह अपने रणनीतिक साझेदारों को रियल-टाइम सूचना सहायता देता है। यह किसी से छिपा नहीं है कि आधुनिक संघर्षों में सूचना की गति ही निर्णायक भूमिका निभाती है। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने उल्लेखनीय कार्य किए हैं, लेकिन निगरानी सैटेलाइट्स के नेटवर्क और निजी भागीदारी के मामले में अभी भी लंबा रास्ता तय करना बाकी है। अंतरिक्ष क्षेत्र में भी यदि निजी कंपनियों को खुलकर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने, प्रयोग करने और असफल होने की स्वतंत्रता नहीं दी गई, तो हम केवल उपलब्धियों की गिनती करते रह जाएंगे, क्षमता का विस्तार नहीं कर पाएंगे।

आने वाले समय का सबसे खतरनाक युद्ध साइबर युद्ध होगा। इसमें न तो सीमा रेखाएं मायने रखेंगी और न ही पारंपरिक हथियार। बैंकिंग सिस्टम, बिजली ग्रिड, संचार नेटवर्क, रेलवे, एयर ट्रैफिक कंट्रोल और सैन्य कमांड सिस्टम - सब कुछ एक साथ ठप किया जा सकता है। पिछले वर्ष का एक जीता-जागता उदाहरण माइक्रोसॉफ्ट के सिस्टम का फेल होना है। यह चाहे किसी भी प्रकार की त्रुटि से हुआ हो, एक आउटेज हुआ और लगभग पूरी दुनिया काफ़ी लंबे समय तक बाधित रही। इसके पीछे क्या कारण रहे होंगे, इसकी आज तक किसी को स्पष्ट जानकारी नहीं है। इतने बड़े मुद्दे को न तो अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने गंभीरता से उठाया और भारत की मीडिया का तो सवाल ही पैदा नहीं होता।

भारत के पास दुनिया के सर्वश्रेष्ठ आईटी पेशेवरों और साइबर विशेषज्ञों में से कई हैं, लेकिन वे या तो विदेशी कंपनियों में काम कर रहे हैं या देश में स्पष्ट नीति के अभाव में सीमित अवसरों से जूझ रहे हैं। सरकार को यह समझना होगा कि साइबर सुरक्षा में निवेश कोई वैकल्पिक खर्च नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा की अनिवार्यता है। यहां भी सरकार को पूंजी लगाने की आवश्यकता नहीं, बल्कि निजी कंपनियों को भरोसा, अधिकार और प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है।

मूल प्रश्न यही है कि समस्या नीति की है या नीयत की। जब सरकार बार-बार कहती है कि देश के पास टैलेंट की कमी नहीं है, तो फिर उस टैलेंट को अवसर देने में संकोच क्यों? रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर टैक्स छूट देना, प्रक्रियाओं को सरल बनाना और निजी क्षेत्र को रणनीतिक क्षेत्रों में भागीदार बनाना कोई राष्ट्रविरोधी कदम नहीं, बल्कि राष्ट्रहित में उठाया गया साहसिक निर्णय होगा। दुनिया का अनुभव यही बताता है कि सरकारें जब नियंत्रक से अधिक सक्षमकर्ता की भूमिका निभाती हैं, तभी नवाचार फलता-फूलता है। भारत को भी यह स्वीकार करना होगा कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में छूट देना कोई नुकसान नहीं, बल्कि भविष्य में कई गुना लाभ देने वाला निवेश है।

निष्कर्ष: यदि भारत आज रिसर्च एंड डेवलपमेंट को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल नहीं करता, यदि निजी क्षेत्र को रक्षा, अंतरिक्ष और साइबर जैसे क्षेत्रों में खुलकर काम करने की अनुमति नहीं देता, तो आने वाले वर्षों में हम केवल दूसरों की तकनीक खरीदने वाले उपभोक्ता बनकर रह जाएंगे। आत्मनिर्भरता का सपना भाषणों से नहीं, बल्कि अनुसंधान में निवेश और भरोसे की नीति से साकार होगा।

भारतीय कंपनियों एवं सरकार की स्थिति आज भी यह है कि वे विदेश से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर अधिक भरोसा करती हैं, न कि अपने देश में नई टेक्नोलॉजी के विकास पर। यहीं से एक-दूसरे पर निर्भरता का खेल शुरू हो जाता है। हमें इससे बचना चाहिए, और सरकार को स्वयं यह भली-भाँति मालूम है कि आने वाले समय में कौन, कब और किसका स्विच ऑफ कर देगा - इसका किसी को पहले से पता नहीं होगा।

आज निर्णय लेने का समय है। अन्यथा कल इतिहास हमसे यही पूछेगा-जब अवसर था, तब हमने संकोच क्यों किया? पूरे देश में खेती किसानी के नाम पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भारत सरकार का एक सफेद हाथी के रूप में खड़ा हुआ है और सरकारों द्वारा अरबो रुपए हर साल इनके ऊपर खर्च किया जाता है और शायद सरकारी विभागों में अगर जमीन देखी जाए तो इस डिपार्टमेंट के पास तीसरे या चौथे नंबर की सबसे ज्यादा जमीन की मिलकियत हो सकती है और सबसे ज़्यादा कर्मचारी और अधिकारी शायद इस डिपार्टमेंट में होंगे लेकिन इनके द्वारा दिए जाने वाले परिणाम आशाजनक नहीं हैं।

रोटेरियन सुनील दत्त गोयल
महानिदेशक, इम्पीरियल चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री।

राशिफल

पंडित अनिल शर्मा

सोमवार 23 फरवरी, 2026

फाल्गुन मास, शुक्ल पक्ष, षष्ठि तिथि, सोमवार, विक्रम संवत 2082, भरणी नक्षत्र सायं 4:34 तक, ब्रह्म योग दिन 10:19 तक, तैतिल करण प्रातः 9:10 तक, चन्द्रमा आज रात्रि 10:12 से वृष राशि में संचार करेगा।

गृह स्थिति: सूर्य-कुम्भ, चन्द्रमा-मेष, मंगल-मकर, बुध-कुम्भ, गुरू-मिथुन, शुक्र-कुम्भ, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह

आज रवियोग सायं 4:34 तक रहेगा। आज गोरुपिणी छठ है। आज मंगल कुम्भ में दिन 11:50 पर प्रवेश करेगा।

श्रेष्ठ चौघड़िया: अमृत सूर्योदय से 8:26 तक, शुभ 9:51 से 11:15 तक, चर 2:05 से 3:30 तक, लाभ-अमृत 3:30 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 7:30 से 9:00 तक। सूर्योदय 7:01, सूर्यास्त 6:20

मेष
मानसिक तनाव दूर होगा। मनः स्थिति में सुधार होगा। परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक सफलता से आत्मविश्वास बढ़ेगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

वृष
घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। समय अनर्गल कार्यों में खराब हो सकता है। मन में असंतोष बना रहेगा। खान-पान के कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है।

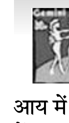

मिथुन
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा।

कर्क
व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। चलते कार्यों में प्रगति होगी। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। धार्मिक कार्यों में धन खर्च हो सकता है।

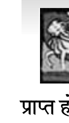

सिंह
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी।

कन्या
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। आज बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। यात्रा में दुर्घटना का भय है।

तुला
परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

वृश्चिक
विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। अस्त-व्यस्त दिनचर्या व्यवस्थित होने लगेगी। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

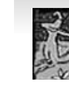

धनु
परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। आज समय रचनात्मक कार्यों में व्यतीत होगा। महत्वपूर्ण कार्यों के संबंध में सोच-विचार हो सकता है।

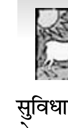

मकर
घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। सुख-सुविधाएं बढ़ेगी। अतिथियों के आगमन से उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक कार्यों से संबंधित आर्थिक समस्या का समाधान हो सकता है।

कुंभ
घर-परिवार में शुभ संदेश प्राप्त होंगे। मित्रों/परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। महत्वपूर्ण कार्यों से संबंधित वार्ता सफल रहेगी।

मीन
आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक सुविधाएं बढ़ेगी। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।